RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-02
February-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

भूमंडलीकरण एवम् वित्तीय संस्थायें

निलेश पंत

शोध छात्र, जी0बी0 पंत संस्थान, प्रयागराज

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 20 February 2019

Keywords
ब्रेटन वुड्स, गैट, अमरीका एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान।

ABSTRACT

भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विश्व के अनेक देश सूचना और तकनीकों के माध्यम से आपस में जुड़ जाते हैं। विश्व में एक स्थान पर होने वाली घटना सुगमतापूर्वक पहुँच जाती है। यातायात के माध्यम से व्यापार में भी वृद्धि देखी जा सकती है। भूमण्डलीकरण को लेकर दो प्रकार की विचारधाराओं को देखा जा सकती है, प्रथम–भौतिक संसाधन एवं तकनीकी का इस्तेमाल करना पश्चिमी प्रकार का भूमण्डलीकरण माना जा सकता है। वहीं द्वितीय परिभाषा में संसाधन के साथ–साथ वैचारिक समन्वय भी आवश्यक माना गया है क्योंकि मनुष्य की भौतिक आवश्यकता संतुष्ट नही होती है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि कैसे मानव उपलब्ध संसाधनों का उचित इस्तेमाल करे तथा मानसिक संतुष्टि को प्राप्त करें। अर्जुन अप्पादोराय ने भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया में ग्रामीण जीवन को भी समावेश किया जिसको वो 'ग्लोकलाइजेशन' नाम देते हैं इसमें वैश्वीकरण एवं घरेलू स्तर पर समन्वय स्थापित कर नागरिक अपना विकास करता है लेकिन वैश्विक स्तर पर भूमण्डलीकरण को आगे बढ़ाने का कार्य प्रथम विचारधारा के आधार पर भी विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन नीचे किया गया है।

आर्थिक पुर्ननिर्माण और व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से पश्चिमी देशों ने मिलकर चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया, जिसने बिना किसी बाधा और विरोध के विश्व में मुक्त व्यापार का मार्ग खोल दिया। ये संस्थाएँ हैं– ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड), विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक) गैट (जी.ए.टी.–जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ (आयात कर)।

ब्रेटन वुड्स विनिमय–दर प्रणाली (ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम) : अमीर देशों की इच्छानुसार उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम ब्रेटन वुड्स विनिमय–दर प्रणाली ने किया। सन् 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में विश्वविख्यात अर्थशास्त्री जॉन मेवार्ड कीन्स के नेतृत्व में अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। उनके बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समझौता हुआ, जिसे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट (ब्रेटन वुड्स समझौता) के नाम से जाना गया। इस समझौते के अंर्तगत पहली बार अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन–देन के संबंध में एक सर्वमान्य 'कानूनी' मसौदे पर विभिन्न देशों ने हस्ताक्षर किए।

इस समझौते से पहले अंतरराष्ट्रीय लेन–देन और व्यापारिक विनिमय में 'सोने' को मानक बनाया जाता था, मगर सोने के साथ कठिनाई यह थी कि वह विभिन्न देशों की व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार सोने के मात्रक को ऊपर–नीचे नहीं किया जा सकता था, जिसके कारण प्रायः विभिन्न देशों में आर्थिक संकट गहराने लगता था। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में सोने के इस गैर लचीलेपन को दूर किया गया। सभी सदस्य देशों की मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर और सोने के संदर्भ में मूल्यांकित किया गया। अमेरिकी डॉलर के अनुपात में सभी मुद्राओं की विनिमय–दर को वैसे ही निर्धारित किया गया, जैसे कभी सोने के संदर्भ में तय हुआ था। सिद्धांत रूप में डॉलर की यह स्थिति हो गई थी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के बदले सोना दिया और लिया जा सकता था। इस तरह डॉलर, जो अमेरिकी मुद्रा था, अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भी बन गया। ब्रेटन वुड्स समझौते को चलाए रखने के लिए अमेरिकी डॉलर के मूल्य को बनाए रखना जरूरी हो गया। इस तरह विश्व का व्यापारिक और व्यापारिक और वित्तीय विनिमय अमेरिकी डॉलर पर निर्भर हो गया। इस तरह अमेरिकी निर्यात की मात्रा आयात की मात्रा से अधिक (ट्रेड सरप्लस) होना आवश्यक सा हो गया। डॉलर की स्थिति यह हो गई कि किसी भी देश के उत्पाद के आयात के बदले अमेरिकी उत्पाद का निर्यात जरूरी नहीं था, डॉलर देकर काम चलाया जाने लगा। डॉलर अंतरराष्ट्रीय निनिमय का साधन हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड) : भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के अंतगर्त निहित शर्तों को पूरा करने और विभिन्न देशों के भुगतान–संतुलन में पैदा हुई बाधाओं का निवारण करना था। एक तरह से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों का केंद्रीय बैंक बन गया। सदस्य देश अपनी मुद्रा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा करा देते और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बदले में सदस्य देशों के भुगतान–संतुलन में आई बाधाओं को दूर करने

RRIJM 2015, All Rights Reserved

के लिए अपने कोष से ऋण देने लगा। प्रारंभिक दौर में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वास्तविक कार्य शेयर बाजार के सट्टेबाजों से ब्रेटन वुड्स प्रणाली की रक्षा करना था। साथ ही विदेशी मुद्रा बाजार में सदस्य देशों की मुद्राओं को सहारा देना था। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को अल्पावधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता था, ताकि भुगतान–संतुलन में उन्हें कठिनाई न आए। बाद में यही (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) तीसरी दुनिया के (विकासशील) देशों के लिए गले की हड्डी सिद्ध हुआ, क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण के कारण ऋण की सुविधाएँ नहीं दी गई थीं, अपितु तीसरी दुनिया के देशों पर कब्जा करने के उद्देश्य से नई टेक्नोलॉजी देन व उन्हें आर्थिक विकास के नाम पर अधिक–से–अधिक ऋण उपलब्ध कराया गया था, ताकि जब वे ऋण के बोझ तले इस सीमा तक दब जाएँ कि उसे चुकाने की स्थिति में न हो, तो उन्हें विवश किया जा सके कि वे विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने देश में प्रवेश देकर व्यापार करने की छूट दें। इसलिए उन्हें ऋण देते समय ऐसे कई नियम और शर्तें उनपर थोपी गईं, जिनसे उस देश की व्यवस्था में बाध्यकारी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाए। अंततः देश में सामाजिक उथल–पुथल और अराजकता का वातावरण फैल जाए और वे भूमंडलीकरण का नारा देकर तथा 'ग्लोबल विलेज' (विश्वग्राम) सुनहरा सपना दिखाकर विकासशील को ठग सकें।

विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक) : भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरह विश्व बैंक का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। विश्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रों के विकास–कार्यों एवं उनके आर्थिक पुर्ननिर्माण के लिए लंबी अवधि का ऋण प्रदान करना था, ताकि विश्व बाजार में मुक्त व्यापार और प्रतिस्पर्धा से बचने का कोई बहाना उन देशों के पास न रहे। विश्व बैंक का गठन विश्व के संपन्न देशों की पूँजी से हुआ। उसमें अमीर देशों ने सकल घरेलू उत्पाद और अन्य कारकों के अनुपात में पूँजी लगाई है। विश्व बैंक अन्य राष्ट्रों की उन परियोजनाओं के लिए कम ब्याज–दरों पर दीर्घावधि के लिए ऋण लेना संभव नहीं होता। विभिन्न राष्ट्रों की परियोजनाओं को विश्व बैंक जो ऋण प्रदान करता है, उसकी अदायगी से शक्तिशाली और संपन्न राज्यों का अर्थतंत्र सुदृढ़ होता है। ऋण लेने वाले देश इस ऋण की अदायगी अमीर देशों का अपने देश के श्रेष्ठतम उत्पादन का निर्यात करके करते हैं।

गैट या विश्व व्यापार संगठन (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन) : द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् जब संपन्न राष्ट्र गहरे आर्थिक संकट की चपेट में थे, तब युद्ध से बरबाद या प्रभावित राष्ट्रों ने पहले अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने की विवशता से आयात और निर्यात की जानेवाली वस्तुओं पर शुल्क लगा दिया, ताकि उनके उत्पादन अन्य देशों के उत्पादन के मुकाबले बाजार में प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। इस मुक्त बाजार हेतु उत्पादनों पर शुल्क लगाकर राष्ट्रों ने जो बाधाएँ खड़ी की थीं उन बाधाओं को अमेरिका हटाना चाहता था, ताकि विश्व में मुक्त व्यापार का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसी कारण राष्ट्रों के बीच शुल्क और व्यापार पर एक सामान्य समझौतों के लिए 'गैट' संस्था का संगठन हुआ, जो सन् 1955 की शुरूआत में 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन' (विश्व व्यापार संगठन) के नाम से जानी जाने लगी। विश्व व्यापार संगठन के गठन के साथ ही विश्वव्यापी आर्थिक सहयोग के नए युग की शुरूआत की घोषणा की गई और कहा गया, 'एक ऐतिहासिक उपलब्धि, जो विश्व अर्थव्यवस्था को प्रबल करेगी और समूची दुनिया में अधिक व्यापार, अधिक पूँजी–निवेश, अधिक रोजगार और अधिक आय के अवसर पैदा करेगी।'

विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सदस्य देशों की एक न्यायोचित और अधिक मुक्त बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में अपने लाभ तथा हित–साधन के लिए कार्य करने की भावना उजागर होती है। इस संगठन के देशों ने एक के बाद एक समझौते करके व्यापारिक प्रतिबंध या बाधाओं को खत्म कर शक्तिशाली और संपन्न देशों के अनुकूल उनके हित में कार्य किया। संपन्न देशों के हित को साधनेवाले इस संगठन ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत व्यापार–नियमों का निर्माण कुछ इस प्रकार से किया गया कि विकासशील देश मुक्त बाजार व्यवस्था के अंतर्गत काम करके आसानी से अपने अर्थतंत्र को विकसित देशों के अधीन होने दें। वस्तुतः गैट समझौते के माध्यम से पूँजीवाद का आक्रमण सभी विकासशील देशों पर हुआ। विश्व व्यापार संगठन की ओट में विकसित देशों ने दुनिया के अन्य देशों का आर्थिक दोहन करने की रणनीति तैयार की है।

विश्व व्यापार संगठन चार सिद्धांतों पर आधारित है, जो इस प्रकार है–

1. राष्ट्रों को अपने व्यापारिक प्रतिबंध कम करने पड़ेंगे।
2. साधारण व्यापारिक प्रतिबंध समान रूप से सभी राष्ट्रों के विरूद्ध लगाए जाने चाहिए या सभी राष्ट्रों को व्यापार के लिए सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए यानी व्यापार में विशेष रियायत देकर किसी राष्ट्र को संरक्षण नहीं देना चाहिए।
3. अगर कोई राष्ट्र शुल्क बढ़ाकर प्रतिबंध खड़ा करता है तो उससे, जिन राष्ट्रों को व्यापारिक क्षति होगी, उसकी पूर्ति शुल्क बढ़ानेवाले राष्ट्र को करनी होगी।
4. व्यापारिक मतभेदों या झगड़ों का सलाह या सदस्य देशों के पंच निर्णय से निबटारा होगा।

वे राष्ट्रों को भूमंडलीकरण की ओर धकेल रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इन सिद्धांतों से समझौता के बाद गरीब या औद्योगिक दृष्टि से कमजोर देशों के बाजार पर संपन्न और शक्तिशाली देशों का कब्जा होने लगता है। इसलिए इस संगठन के विरूद्ध अनेक देशों में भारी आंदोलन हुए और कई देशों में आंदोलन की तैयारी चल रही है। उक्त सिद्धांतों पर सहमति बनाकर राष्ट्र प्रायः सम्मेलन करते रहे। राष्ट्रों के बीच खड़े किए गए शुल्क और कोटा के प्रतिबंधों को उन्होंने धीरे–धीरे कम किया तथा मुक्त बाजार के लिए रास्ते तैयार किए। सन् 1993 में विश्व व्यापार संगठन का 'उरूग्वे राउंड' संपन्न हुआ, जिसमें कृषि पर सब्सिडी घटाने और टेक्सटाइल में कोटा खत्म करने

का बड़ा फैसला लिया गया। इसने सेवाओं और बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) में मुक्त व्यापार को बढ़ाया। कुल मिलाकर विश्व व्यापार संगठन की शक्ति अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समझौते को लागू करनेवाले में बढ़ गई। 'उरूग्वे राउंड' ने उन विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुँचाया, जो कृषि तथा टेक्सटाइल पर आधारित थी। भारत भी ऐसा ही एक राष्ट्र था।

अमेरिका द्वारा ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की समाप्ति : ब्रेटेन वुड्स समझौते से अमेरिका को शुरू में सबसे अधिक लाभ हुआ। स्थायित्व, परिवर्तनीयता और विश्व में स्वीकार्य होने के कारण अमेरिकी डॉलर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तित हो गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय विनिमय अमेरिकी डॉलर में किए जाने लगे। भुगतान भी अमेरिकी डॉलर में होने लगे। एक्सचेंज–रेट पैरिटी (विनिमय–दर साम्यता), यानी लेन–देन में डॉलर को सोने के तुल्य मानकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर, इसके अतिरिक्त सरकारी और निजी खजाने को डॉलर में आरक्षित किया जाने लगा। इस बीच पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया के राष्ट्रों की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति हुई। इन औद्योगिक राष्ट्रों ने 'शुल्क' और 'कोटा' के माध्यम से व्यापारिक प्रतिबंधों को लगभग समाप्त कर दिया। भूमंडलीय व्यापारिक व्यवस्था में अमेरिकी डॉलर ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपनी विशेष स्थिति के कारण अमेरिकी डॉलर शिखर पर पहुँच गया; लेकिन शिखर पर पहुँचे डॉलर में अन्य देशों के बाजार के विध्वंस के बीच छिपे हुए थे।

वियतनाम–युद्ध और अमेरिकी कंपनियों द्वारा बाहर के देशों में पूँजी–निवेश करने के कारण अमेरिका का बजट घाटा (बजट डेफिसिट) बढ़ने लगा। इसी बीच अपनी उच्च प्रौद्योगिकी और उत्पादन के सहारे जर्मनी व जापान का ट्रेड सरप्लस (यानी आयात से ज्यादा निर्यात) होने के कारण उनके यहाँ डॉलर का ढेर लगने लगा। सन् 1971 तक नकदी (लिक्विड) डॉलर की देनदारी इतनी अधिक बढ़ गई कि डॉलर की आधिकारिक साम्यता को बनाए रखना कठिन हो गया। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। मुक्त वित्तीय विनिमय के लिए खत्म किए गए प्रतिबंधों का अर्थ यह था कि देश में अचानक अरबों डॉलर आ सकता था, जो डॉलर की आधिकारिक साम्यता को बनाए रखने में कठिनाई पैदा कर देता। इसलिए 15 अगस्त, 1971 को राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर और सोने के वित्तीय संबंध को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस तरह ब्रेटन वुड्स प्रणाली का अपने आप अंत हो गया।

अमेरिका द्वारा ब्रेटन वुड्स प्रणाली को समापत करने की घोषणा का अर्थ यह हुआ कि विश्व के व्यापार या वित्तीय व्यवस्था में अमेरिका ने अपनी मुद्रा (डॉलर) को शिखर पर बनाए रखने और आर्थिक स्थिति को अन्य के मुकाबले श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए मनमानी घोषणाएँ कीं और परिवर्तन किए। जब तक ब्रेटन वुड्स प्रणाली उसकी आर्थिक सर्वोच्चता की गारंटी बनी रही तब तक उसने उसे चलाया। जब डॉलर का वर्चस्व खतरे में पड़ गया तो उसने ब्रेटन वुड्स विनिमय–दर प्रणाली खत्म कर दी। अमेरिका और अमीर देशों द्वारा नियंत्रित भूमंडलीकरण जिस दिन अमेरिकी आर्थिक हितों के विरूद्ध जाएगा, उस दिन अमेरिका द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थाओं के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। अब अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स प्रणाली खत्म करके मिश्रित प्रणाली (हाइब्रिड सिस्टम) लागू कर दी है।

इस तरह से आर्थिक पुनर्निमाण और व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से पश्चिमी देशों ने मिलकर जिन चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया, उनकी व्यापार–नीतियाँ वास्तव में वैश्विक कार्य व्यापार, यानी भूमंडलीय कार्य व्यापार द्वारा सभी को आर्थिक समृद्धि प्रदान नहीं करतीं, बल्कि वे संपन्न और शक्तिशाली देशों के आर्थिक तंत्र में कमजोर देशों को जकड़ती हैं। विकासशील देशों के नागरिकों का भरपूर शोषण व्यापारिक कंपनियों द्वारा किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए–दुनिया के भारत सहित तमाम देशों ने गैट समझौते को स्वीकार कर अपने–अपने देशों की जनता का भविष्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में सौंप दिया है और प्रायोजित नारा दिया है कि भूमंडलीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सकेगी और देश आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ सकेगा; लेकिन सच्चाई यह है कि इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने विकासशील देशों में भूमंडलीकरण का नारा उछालते हुए मुक्त बाजार व्यवस्था के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश द्वारा अपनी समृद्धि की संभावनाओं को तलाशा है और उनकी समृद्धि की ये तमाम संभावनाएँ टिकी हैं विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक शोषण पर।

संदर्भ ग्रंथ :

1. डॉ० प्रेम सिंह, भूमंडलीकरण का असली चेहरा, आलेख, युवा सांसद, हिन्दी मासिक, सं. डॉ० ए. के. अरूण, नई दिल्ली, सितंबर, 2006
2. डॉ० मुकेश कुमार एवं सुधांशु कुमार संपादक, भूमंडलीकरण और लोकतंत्र, जागृति प्रकाशन, पटना, 2010
3. अतुल कोहली, पॉलिटिक्स ऑफ इकोनोमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, वर्ल्ड डेवलपमेंट, 1989
4. अमित भादुरी और दीपक नैय्यर, इंटेलिजेन्ट पर्सन्स गाइड टू लिबरलाइजेशन, नई दिल्ली, 1896

RRIJM 2015, All Rights Reserved